

**14.52 hrs.**

**GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES AND THE GOVERNMENT OF  
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2005**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 12. Shri S. Regupathy.  
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S.  
REGUPATHY): I beg to move :

"That the Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963 and to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, be taken into consideration."

Mr. Speaker, Sir, the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001 has extended the constitutional embargo on undertaking fresh delimitation of electoral constituencies up to the year 2026 and has simultaneously provided for undertaking the readjustment and rationalization of electoral constituencies, including those reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, based on the population figures for the year 1991 without affecting the number of seats allocated to the States in the Legislative Bodies. The Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003 provides for the readjustment and rationalization of electoral constituencies, including those reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, based on the population figures for the year, 2001.

The Amendment Bill seeks to amend the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 in respect of Pondicherry and the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 to be in line with the amendments made to the Constitution by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001 and the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003.

Now Sir, I beg to move that the Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2005 relating to delimitation of electoral constituencies with respect to the Union territories of Pondicherry and NCT of Delhi be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved :

"That the Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963 and to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, be taken into consideration."

Shri Girdhari Lal Bhargava to move his Amendment. He is not present.

Shri Sandeep Dikshit.

**श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जो दो संशोधन पांडिचेरी और दिल्ली के लिए लाए जा रहे हैं, इनके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि इन राज्यों के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से लोकसभा की सीटें बनायी जाती हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में विधान सभा की सीटें भी बनायी जाएं। जिससे एससीएसटी की जितनी कम्पोजिशन है, उसका पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य उसमें आ जाए।

जितनी एससी, एसटी की कम्पोजिशन सन् 2001 के सैन्सस में पाई गई हैं, सीट्स भी उसी हिसाब से रिजर्व हों, जिनमें दिल्ली की जनता को उस रूप में पूर्ण रिप्रैजेंटेशन मिल सके। जब 1950 में हमारा संविधान बनाया गया और उसके बाद ऐडॉप्ट किया गया, तब बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उनमें जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थे, उनके रिप्रैजेंटेशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिनमें एससी, एसटी के लोग संसद और अपनी-अपनी विधान सभाओं में उतने ही रूप में आए जितना पौपुलेशन में उनका रिप्रैजेंटेशन है। पिछले पचास साल का अनुभव यही दिखाता है कि शुरू में जो सकारात्मक कदम लिए गए थे, उनसे उन तबकों पर बहुत ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ा। उनके विकास पर पड़ा और उनके मुद्दों को संसद और तमाम असेम्बलियों में लाने में यह बहुत ही कारगर उपाय पाए गए। इस कारण मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी संशोधन लाए जाएं। अगले साल जो डीलिटिमिटेशन होने वाला है, उसमें ये दर्शित किए जाएं।

मैं इस मौके पर चंद बातें और दिल्ली राज्य के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली राज्य में भारत सरकार के प्रशासन का काफी अधिक प्रभाव रहता है। दिल्ली न केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों की राजधानी है, बल्कि सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के लोगों की राजधानी है। इसलिए यहां का विकास, यहां की स्थिति के लिए, खासकर संसद के बारे में मुझे मालूम है, संसद के लिए दिल्ली

की विशेष जगह हमेशा रही है। इसकी स्थापना, इसकी जगह, इसका विकास विशेष संसद के इंटरस्ट में रहा है और हर मैम्बर किसी न किसी रूप में दिल्ली को भी अपना घर मानता है। आपने देखा होगा कि तमाम दिग्गज नेता भी किसी न किसी रूप में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आदरणीय इंदिरा जी ने दिल्ली को हमेशा विशेष प्रेम दिया। आदरणीय राजीव जी ने अपना बचपन और बहुत समय दिल्ली में बिताया। गुजराल साहब को एक तरह से हमेशा दिल्ली का माना गया। वर्तमान प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी भी एक तरह से दिल्ली में ही रह रहे हैं। यहां उन्होंने पढ़ाया है, शायद वे यहां पढ़े भी हैं। हिन्दुस्तान का बहुत सा नेतृत्व किसी न किसी रूप में या तो दिल्ली से पढ़ा हुआ है या दिल्ली में आकर बसा है। दिल्ली ने अपार दिल भी दिखाया है। जो व्यक्ति भी दिल्ली आया, वह दिल्ली छोड़कर कभी वापिस नहीं गया। इस मामले में दिल्ली का एक विशेष स्थान रहा है और हिन्दुस्तान की जो समग्र संस्कृति बनी है, उसमें बहुत हद तक दिल्ली का प्रभावी रोल भी रहा है और दिल्ली ने उसे अपने छोटे से रूप में भी दृश्य दिया है। यहां दक्षिण भारत का व्यक्ति आता है, उत्तर भारत का व्यक्ति आता है, पश्चिमी भारत का व्यक्ति आता है और पूर्वी भारत का व्यक्ति भी आता है और दिल्ली आकर दिल्ली वाला कहलाता है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां जगह-जगह से राजनेता भी आए जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी अपना घर किया और दिल्ली के लोगों ने उनको अपने प्रेम से, प्यार से स्वीकारा है। (व्यवधान)

**श्री राम कृपाल यादव (पटना) :** दिल्ली का व्यक्ति दिल वाला भी होता है।

**श्री सन्दीप दीक्षित :** दिल वाला तो है ही। अच्छा हुआ कि आपने यह कहा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि संशोधन के कारण हमारी जनता में जो बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है, वह विधान सभाओं में भी दर्शित होता होगा। लेकिन कुछ छोटी-

मोटी चीजें भी हैं जिन बारे में मैं संसद और तमाम सीनियर कोलीग्स का थोड़ा-बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह माना कि दिल्ली में सबसे बड़ी पर-कैपिटा इनकम रही है। दिल्ली का गरीबी का स्तर भी केवल 8 या 9 प्रतिशत ही है। लेकिन आज भी हर वह व्यक्ति, जो और कहीं से निराश हो जाता है, जिसे शायद अपने राज्य में, अपने घर में जगह नहीं मिल पाती, या जो शायद स्वर्णिम भविष्य की तरफ अग्रसर होता है, उसे दिल्ली में न केवल घर मिलता है, बल्कि उसे दिल्ली में आजीविका के विकल्प भी मिलते हैं और एक ऐसी जगह मिलती है जहां उसे जीवन-यापन करने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जो शायद उनके अपने घरों में नहीं मिल पातीं। चाहे हमारे भाई उत्तर प्रदेश से आए हों, जहां से किसी जमाने में मेरा परिवार भी आया था, चाहे बिहार के लोग रहे हों, चाहे दक्षिण भारत से लोग आए हों, चाहे किसी भी प्रान्त से लोग आए हों, उन्होंने दिल्ली को अपना घर बनाया है। यह बात इससे भी प्रदर्शित होती है कि जब सन् 1991 और 2001 के बीच पूरे हिन्दुस्तान की पौपुलेशन केवल 21 प्रतिशत बढ़ी, दिल्ली की 46 प्रतिशत बढ़ी।

### **15.00 hrs.**

हर साल पांच लाख नये लोग दिल्ली को अपना घर बनाते हैं। दिल्ली की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है या प्रजनन दर है जिससे उसकी अपनी पापुलेशन बढ़ती है, वह बहुत कम है। अगर हम उसी दर के हिसाब से चलें तो दिल्ली की पापुलेशन शायद घटती चली जाये। लेकिन हिन्दुस्तान के बहुत से नागरिक दिल्ली में आते हैं, दिल्ली को अपना घर बनाते हैं। दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वह बिजली की हो, पानी की हो, घर की हो या लॉ एंड आर्डर की हो जिस पर भारत सरकार की हमेशा कृपा रही है। भारत सरकार का दिल्ली की तरफ बहुत प्यार रहा है। धीरे-धीरे ये सभी सुविधाएं दिल्ली में कम होती गयीं। आखिरकार एक सीमा होती है किसी भी सीमित राज्य को, किसी भी सीमित जगह को उन सुविधाओं को उसी रूप में अपने नागरिकों को देने की, जितने कि वह नागरिक अपनी कैपिटल, अपने राज्य से अपेक्षा रखते हैं।

आज आपने देखा होगा, हमारे सारे मैम्बरों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दिल्लीवासियों से बाहर होती जा रही हैं। आज पानी की बड़ी गंभीर समस्या दिल्ली के सामने खड़ी है। दिल्ली में इतनी जमीन नहीं है, नदियां नहीं हैं, पानी के स्रोत नहीं हैं कि हम अपने यहां से पानी निकालकर आप सबको पर्याप्त जल दे सकें। हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम इतने संयंत्र बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकें जिससे 24 घंटे आपको पर्याप्त और अच्छी बिजली मिल सके। दिल्ली में हमने हमेशा प्रयास किया है कि ये सुविधाएं आपको मिलती रहें। जब भी जरूरत पड़ती है, तमाम राज्य बड़े प्यार से, प्रेम से जितनी भी बिजली दे सकते हैं, वह उन्होंने हमें दी है। हमारे पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा जितना भी पानी दे सकते हैं, वह हमें दिया है। इस बात के लिए दिल्ली बाकी राज्यों की हमेशा आभारी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ये राज्य अपनी विवशता के कारण पर्याप्त मात्रा में हमें पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं नहीं दे पाते जिस रूप में दिल्ली को आवश्यक हैं और दिल्ली का हर नागरिक यहां रहने के बाद जिन सुविधाओं की अपेक्षा करता है। जब मैं दिल्ली से बाहर चला जाता हूं, अगर मैं किसी और राज्य में रहता हूं तो शायद अपनी सरकार से वह अपेक्षा नहीं करता, लेकिन दिल्ली आकर यहां का नागरिक होकर वे अपेक्षाएं मेरे मन में आ जाती हैं। इसलिए कुछ रूप में पूरे हिन्दुस्तान का थोड़ा सा दायित्व बनता है कि अपनी राजधानी में हम वे सुविधाएं रखें जो हम खुद अपने राज्य में अपेक्षा करते हैं। ये अपेक्षाएं सबकी मिलकर बनी हैं।

दिल्ली की डेढ़ करोड़ जनता में शायद 30-40 लाख ऐसे लोग होंगे जो पहले से ही दिल्ली के रहे होंगे। बाकी जो एक सवा करोड़ लोग हिन्दुस्तान के सब जगह से आकर दिल्ली को अपना घर बना चुके हैं। हमारे यहां जमीन की बहुत कमी है। आज शहर बनने के कारण अर्बन वैस्ट की समस्या होती है, लैंड फिल की समस्या होती है। दिल्ली में बहुत कम ऐसे क्षेत्र बचे हैं, जिनको हम लैंड फिल के लिए कन्वर्ट कर पायें। मैं मानता हूं और हमारे पड़ोसी राज्यों के लोग भी नहीं चाहेंगे

कि हमारी गंदगी उन तक जाये। लेकिन हमारी भी कुछ विवशताएं हैं। हम कहां तक यह सारा कूड़ा-कड़कट उस सीमित क्षेत्र में देते जायें ? किसी जमाने में खाली जगह होती थी लेकिन आज हमारी जनता वहां भी रहने लग गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मुद्दे और हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार और यहां बैठे हुए संसद सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा। सन् 1985-86 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने बहुत ही दूरदर्शिता के रूप में एक कांसैप्ट बनाया था जिसमें नैशनल कैपिटल रीजन की बात गयी थी। श्री राजीव गांधी जी ने जिस तरह की दृष्टि नैशनल कैपिटल रीजन द्वारा रखी थी, वह अपने आप में क्रंतिकारी थी। उसके बाद समय बदला, राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदला। दुर्भाग्य से श्री राजीव गांधी जी नहीं रहे। राष्ट्र और राज्यों में जो नेतृत्व आया, उन्होंने शायद नैशनल कैपिटल रीजन को वह महत्व नहीं दिया जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एरिया और नैशनल कैपिटल रीजन को देना चाहिए था। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि पड़ोसी राज्यों को किसी न किसी रूप में योगदान देना पड़ेगा। भारत सरकार की सबके साथ समन्वय, सामंजस्य करने की जो भूमिका है, उसको शायद पुरजोर रूप में, कहीं न कहीं कारगर रूप में रखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि दिल्ली के कारण ही हमारे पड़ोसी राज्यों को काफी चीजें उपलब्ध हुई हैं। जो नोएडा का क्षेत्र है, वह उत्तर प्रदेश के विकास को बहुत आगे बढ़ाकर चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना भी हमें करनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के विकास को देखकर एक दूरदर्शिता की नीति लेकर उस क्षेत्र का विकास किया।

इसलिए दिल्ली के लोगों को जहां दिल्ली में जगह नहीं मिल पाती थी, यहां पैसा निवेश करने की जगह नहीं मिल पाती थी, उन्होंने नोएडा में उसी चीज का निवेश किया। इसी तरह हरियाणा राज्य ने भी इसी तरह की दूरदर्शिता दिखाते हुए, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया। गाजियाबाद के भी कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। लेकिन आज वह बात हो गई है कि दिल्ली

अपनी सिमटी हुई जमीन के कारण, अपनी सिमटी हुई नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, अब एक विवशता की तरफ बढ़ रही है कि शायद उसमें अपने में वह क्षमता नहीं बड़ी है कि वह अपने अंदर की शक्तियों को और जो लोगों की क्षमताएं हैं, अपनी जमीन में, अपनी सीमित क्षमताओं के अंदर पूर्ण कर सके। इसलिए हमें इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हमारे पड़ोसी राज्य आज दिल्ली राज्य के विकास में उसी रूप में सहयोगी बनकर चलें जिस रूप में दिल्ली के विकास से सब राज्यों को कहीं न कहीं फायदा मिला है।

वास्तव में, दिल्ली अब केवल दिल्ली की नहीं रही है। दिल्ली एक राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में बनती चली जा रही है। दिल्ली किसी व्यक्ति की नहीं है। दिल्ली हमारे लिए, हम सबके लिए राजधानी है। हम सबके लिए गर्व की चीज भी है। दिल्ली ने इतना प्यार हम सबको दिया है। मेरे ख्याल से एक समय अब ऐसा आ रहा है कि न केवल हम और हमारे पड़ोसी राज्य बल्कि पूरा देश थोड़ा-बहुत यह ध्यान दे कि दिल्ली के आगे आने वाले समय में हम किस तरह से इसको एक रूप दे सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिन्दुस्तान की जो जनसंख्या है, उसकी 35 प्रतिशत जनसंख्या करीब शहरों में रहने लगी है। आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, 40-42 प्रतिशत के करीब हम पहुंच जाएंगे और 15 या 20 साल में हिन्दुस्तान केवल अपने गांव में नहीं रहेगा। हिन्दुस्तान की कम से कम 50 प्रतिशत जनता अब शहरी इलाकों में रहना शुरू कर देगी। आने वाले समय में यह एक चुनौती भी है और समस्या भी है। हमें कहीं न कहीं मिलकर, एक रूप में शहरी विकास की तरफ भी देखना पड़ेगा। शहरी हिन्दुस्तान किस रूप में बने, शहर में आने वाले व्यक्ति की अपेक्षाएं उस व्यक्ति से बिल्कुल बदल जाती हैं जो गांव में है। गांव में वह आज भी सर पर मटका रखकर दो कि.मी. तक पैदल चलकर पानी ले आता है। उसको अगर तीन घंटे बिजली मिलती है तो वह इसी में संतोष कर लेता है कि उसका पंप चल गया और उसकी आधी एकड़ जमीन में पानी पड़ चुका है। अगर उसको शौच



के लिए जाना होता है और उसको अगर खुला मैदान मिल गया है तो संतोष से वह वहां चला जाता है। इन सब बातों में वह किसी भी बात के लिए सरकार की तरफ नहीं ताकता है। लेकिन जैसे ही वह शहर आ जाता है, वह चाहता है कि मेरे घर की दहलीज पर या घर के अंदर या घर के बिल्कुल बाहर या फिर कम से कम 15 फुट दूर कोई ऐसा सार्वजनिक नलका हो, जहां सरकार से हमें स्वच्छ पानी मिल सके। वह चाहता है कि हमारे घर में नहीं तो सार्वजनिक रूप में कहीं न कहीं शौच का इंतजाम हो। वह चाहता है कि बिजली 24 घंटे नहीं तो कम से कम 18-20 घंटे मिले। वह चाहता है कि जो और सुविधाएं हमारे पड़ोस में जोरबाग में या मोतीबाग में रहने वाले व्यक्ति को मिलती हैं, जैसे वह खुली हवा में रह पाता है, उसको अच्छी बस सेवा मिलती है, वही मुझे और मेरे बच्चों को भी मिले।

अंत में, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा और यह मैं जानता हूं कि सरकार इस पर सोच रही है लेकिन और पुरजोर तरीके से शहर किस तरह से आगे बढ़ें, इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। अगर एनसीआर के बारे में थोड़ी और मेहनत की जाए तो दिल्ली की जो तमाम छोटी-छोटी समस्याएं हैं, इसमें भारत सरकार बहुत कारगर रूप से हमेशा दिल्ली की सहयोगी रही है कि दिल्ली एक आदर्श राज्य और आदर्श शहर के रूप में बढ़ता चला जाएगा और पूरे हिन्दुस्तान को एक तरह की लीडरशिप देता रहेगा। मैं इसी के साथ इस संशोधन का पूर्णतः समर्थन करता हूं। . (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajay Maken - not present.

Shri C.K. Chandrappan.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, this Bill is brought to achieve a very limited purpose of effecting delimitation of constituencies in Delhi. As it does not fall within the purview of the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001 and the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, this Bill seeks to amend the Government of Union Territories Act, 1963 and the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. I support the purpose of the Bill, but I take this opportunity to know from the Minister to what extent the work of delimitation has progressed and whether he will be able to assure this House that the future elections to the State Assemblies will take place on the basis of the present exercise that is going on because I understand that only in few States, the work of Delimitation Commission is now progressing. In the year 2006, there are four or five State Assemblies that will go to elections - Kerala, West Bengal, probably Tripura and also Tamil Nadu.

Will the elections in these States be based on the present delimitation exercise, which is going on?

Secondly, I do not know how the Government will solve the problem about which the friend from Delhi was mentioning just now in the House. He was saying that the population increase in this metropolitan city is about 46 per cent. It means, there is an increase of almost 50 per cent in the population, and the present delimitation will only delimit the constituencies on the basis of the existing population. The number of seats, as I understand, is not going to be increased. It means that very unwieldy constituencies will be created. Perhaps, adjustments will be made in such a way that the present unwieldy constituencies will be readjusted a little to make some marginal changes in it. But the constituencies will be much bigger in size -- in terms of population -- than the constituencies elsewhere in the country. I find that this amendment does not bring any solution to this problem.

The hon. Member who spoke before me was also mentioning about the issue of urbanisation. I feel that more employment facilities should be made available in the State and in the villages around Delhi if the fast-paced urbanisation has to be stopped. If this objective is achieved, then the people will

not migrate to the cities looking for better facilities, and better employment opportunities for a reasonable survival. If it is not provided in the States nearby, then it will become a very big problem. It is not only the case of Delhi, but this problem is being faced by all the mega-cities in the country. They are reaching a point of explosion, and it would create a big problem for all of us.

I was recently reading an article in the Press saying that the Indian cities are becoming the biggest metropolitan cities in the world. It is not something about which we should be very proud of. It only shows that the rural life is miserable and is unattractive, and the people are migrating to cities craving for better opportunities and facilities. Probably, they are running after a mirage thinking that life will be better in the cities. The life in the cities, as it is today, does not provide a better opportunity or a better quality of life.

I do not want to discuss this issue further in this context, but it is an important issue with regard to the cities where the delimitation is proposed. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is thinking on these lines to improve the conditions around the city. If this measure is taken, then the issue of urbanisation will not become a serious threat to us. Secondly, are the elections -- which are going to take place in the country -- going to be based on the present delimitation exercise, which is going on?

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir. This is a very simple Bill. There is nothing much to say on it because the two amendments, namely, the 84<sup>th</sup> Constitutional Amendment Act 2001, and 87<sup>th</sup> Constitutional Amendment Act 2003 set two directions. It states that there will be no increase of seats up to the year 2026, and consequently, there should be even distribution of seats among the existing number of constituencies, during this period, to face the growing population in every State and Union Territory. These two directions are being implemented in various States, besides reserving seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that they can get proper representation. The same thing is to be implemented in the case of Delhi and Pondicherry, and that is the purpose of this Amendment. I support this Amendment. We have to pass this Amendment to enable the proper conduct of electoral process in Delhi and Pondicherry.

The only thing I would like to mention is that population in the National Capital Territory of Delhi has increased substantially. This has been mentioned by the two earlier speakers that it is growing very fast. This is happening due to migration. This migratory nature creates an uncertainty as to whether they will be voters next year. It is because of the fact that they will be voters here in one year and next year they may migrate to some other place. This migratory nature of the voters is causing a problem and that should be taken care of.

Secondly, the area also should be taken into account. In Delhi, I have seen that there are certain constituencies where more than three lakh population is there, and there are certain constituencies where one lakh or around one lakh population is there. The minimum or the optimum level of the population size should be around two lakhs. To bring them more or less at par, these changes will have to be effected at various places.

As you know in other States, the national parties are represented in the Delimitation Committee. In Delhi, I think, only Congress and BJP are represented in the Delimitation Committee, and other national parties do not have any representation in that. Therefore, recognised national political parties, like the CPI (M), CPI, SP and BSP, should have representation in the Committee. Of

course, those two parties will do their job, but still, there will remain some apprehension that things may not be worked out properly. I think, this matter should be considered, and I would request the Government to give a thought to it.

These two things, that is, equity of size and voters of the constituency, should be kept in mind and you should see as to how it could be done conveniently. Secondly, recognised national parties should be involved in the delimitation process in these two States of NCR Delhi and Pondicherry. The Government should keep these things in mind.

With these words, I support the Amendment Bill.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Deputy-Speaker, Sir, as a Member representing the Union Territory of Pondicherry, I wholeheartedly support the Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill brought by the hon. Minister of State for Home, Shri Regupathy. I support this Amendment Bill. This will place the Union Territory of Pondicherry at par with the rest of the country. When all the States are undergoing the process of delimitation, the Union Territory of Pondicherry or the National Capital Territory of Delhi cannot remain in isolation.

Therefore, it brings uniformity between the Union Territories and the States and hence we support the amendment to the Bill. At the same time, I would like to bring to the notice of the hon. Minister of Law and Justice, who is present here, one important issue pertaining to the Union Territory of Pondicherry.

The Delimitation Commission has completed its exercise as far as the Union Territory of Pondicherry is concerned. We understand that the Commission has informed the Ministry of Law and Justice, the hon. President, and the Legislative Assembly of the Union Territory of Pondicherry also, but we do not know from which date this delimitation exercise will come into force. As hon. Member Shri Chandrappan has asked whether it will come into force from the next Assembly Elections or not. It has to be known to the people of Pondicherry.

The second issue which I would like to bring to the notice of all concerned here is that the Union Territory of Pondicherry has been making great strides both in the economy as well as in the society. The Union Territory of Pondicherry is today one of the most urbanised regions in the country. To give you the figures of the 2001 Census, this is the fourth highly urbanised area in the country. The population of this Territory, which was just 3.69 lakhs in 1961, has escalated to 9.07 lakhs. However, the number of constituencies still remain constant. The population has trebled in the last 30-40 years but the number of constituencies remains constant at 30. This has created a lot of problems of representation of the people. Of course, it is not within the reach of the Minister or the reach of the

people, but the feeling of the people of Pondicherry is that the number of Assembly constituencies must be increased in proportion to the growth of population.

Therefore, if you put an embargo on 30 seats as decided when the population was 3.69 lakhs and the population according to the 2001 Census is 9.07 lakhs, there is no parity and there is no justice. Therefore, if it is possible, the number of constituencies in the Union Territory of Pondicherry must be increased.

Another peculiar characteristic of the Union Territory of Pondicherry is that it is geographically isolated. The capital of the Union Territory of Pondicherry is Pondicherry. The other region Karaikal is far away - 154 kilometres away - from the city. Mahe, which is located in Kerala, is 890 kilometres away from Pondicherry. Yanam, enclaved in Andhra Pradesh, is again 800 kilometres away from Pondicherry. Therefore, all the four regions are highly scattered and there should be due representation to them. The delimitation exercise carried out by the Delimitation Commission of India has changed a number of constituencies in each one of these regions. The Hon. Minister of Law and Justice is keenly listening to what I say. He should be able to do something about it.

**15.23 hrs.** (Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

Till the Delimitation Exercise, Karaikal had six representatives. Today, it is reduced to five. Mahe region, which is in Kerala, which had two representatives, will now have only one. Yanam will have the status quo on the number of seats. Pondicherry will have 23 constituencies. Therefore, this has created a lot of heartburning among the people. The number of representatives in Karaikal now, with all the development attached to the Members of the Legislative Assembly, has now come down from six to five. Therefore, if it is within the reach of the Ministry of Law and Justice, I would request the hon. Minister on behalf of the people of Pondicherry that the status quo should be maintained. If you say that the number of seats should remain constant, it should be applicable to the region-wise number of seats also. If the total seats in Pondicherry must be 30, then the total number of seats which were existing in Karaikal, that is six, must

remain six. If the number of seats in Mahe was two, that must also be kept intact. That would only bring about social justice to the people.

Therefore, I would recommend to the Government that the number of seats in the Union Territory of Pondicherry must be increased because nowhere in the country the demographic growth has been as phenomenal as in the Union Territory of Pondicherry. While the national growth rate is only 2.1 per cent per annum, the growth rate of Pondicherry is about 2.5 per cent, which existed for the country as a whole in 1951. Therefore, it should be done.

The delimitation exercise that is carried out is sound in several respects. For example, the number of SC constituencies which existed earlier remained the same and it bears a proportion to the representation of the SC population to the total population.

Therefore, it is accepted by the people. Therefore, the Delimitation Constituencies has done a good job to Pondicherry. I would say that if some more amendments can be brought to the Union Territory Act of Pondicherry, 1963, it would serve better the political process of the Union Territory of Pondicherry.

With these few words, I wholeheartedly support the amendment brought by the hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs.



THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. REGUPATHY): Hon. Chairman, Sir, I would like to thank all the hon. Members who have supported this Bill. First of all, I want to say that the amendment is only for a limited purpose.

The Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001 has further extended the Constitutional embargo on fresh allocation of seats consequent upon the completion of each census up to the year 2026 A.D. It simultaneously provides for undertaking readjustment and rationalisation of electoral constituencies, including those reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, based on the population census for the year 1991 without affecting the overall number of seats allocated to the States in the Legislative Bodies. So, without disturbing the existing seats, this amendment is carried out regarding the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Articles 81 and 82 of the Constitution provide for readjustment of seats in Parliament and article 170 in respect of Legislative Assemblies in the States on the basis of population.

The Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003 provides for undertaking readjustment and rationalisation of electoral constituencies, including those reserved for the Schedule Castes and the Scheduled Tribes based on the population census for the year 2001. This exercise, however, does not affect the overall number of seats allocated to the States and Union Territories in the Legislative Bodies.

Regarding the specific query from the hon. Member, Shri Chandrappan, I would like to state that the Delimitation Commission has been constituted by the Ministry of Law and Justice which has taken up the work of delimitation. I hope it will complete its exercise well in time. Only then can I say as to whether it will be made applicable for the coming elections or not. . (*Interruptions*) The work is going on. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I want to seek a clarification. The hon. Minister said that the Delimitation Commission would complete its work well in time. That we all know. There are elections for State Assemblies in the coming

year. I would like to know as to whether these elections would be based on the report submitted by the Delimitation Commission.

SHRI S. REGUPATHY: There are elections for the State Assemblies in 2006. If the delimitation process is completed well in time, then it will . (*Interruptions*) The delimitation process is going on. . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Delimitation of constituency is going on in the country as a whole, both for Parliamentary and State Assembly constituencies, and the report of the Delimitation Commission will be completed.

SHRI S. REGUPATHY: The Law Department is doing the work on delimitation. . (*Interruptions*) We cannot commit a date. I can only say that it will submit the report well in time. . (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Will the exercise being carried out by the Delimitation Commission be fruitless? There is a spell of elections to the State Assemblies which would take place in the next year or a year after. If the delimitation work is over insofar as those States are concerned, will you make a commitment that you would hold the elections on the basis of the report of the Delimitation Commission? . (*Interruptions*)

SHRI S. REGUPATHY: How can I make that commitment? The Department of Law and Justice has constituted a Commission and it is doing its job. We expect that it would complete its exercise well in time. . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The Eighty-seventh amendment to the Constitution is specific that the number of constituencies will not change because of population as family planning is not implemented properly.

. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Will the same be made applicable to the Union Territories also?

SHRI S. REGUPATHY: Yes, Sir.

With a view to fall in line with the 84<sup>th</sup> and the 87 Constitutional Amendments, amendments are required in the Government of Union Territories Act, 1963 and the Government of NCT of Delhi Act, 1991.

I come to the existing provisions of the Government of Union Territories Act, 1963. Sub-section (5) of section 3 of the Government of Union Territories Act, 1963 provides as follows: The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the Union Territory under sub-section (4) shall bear as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the Union Territory or of the Scheduled Tribes in the Union Territory, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the population of the Union Territory.

**श्री रघुनाथ झा (बेतिया) :** सभापति महोदय, माननीय कानून मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। हम बिहार से आते हैं। बिहार में विधान सभा का चुनाव हुआ। वहां कब तक डीलिटिमिशन करेंगे, चूंकि अभी तक वहां के सदस्यों ने शपथ भी नहीं ली है। उनको दूसरी किसी हैसियत से भी यहां बुलाया नहीं जाता है। उसमें जो पुराने संसद सदस्य हैं वे तो आ जाते हैं लेकिन विधान सभा के जो नए सदस्य हैं, वे नहीं आ पाते हैं। उनको शपथ नहीं दिलाने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इसलिए बिहार के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय कब तक होगा, क्या कोई वाया मीडिया निकालेंगे जिससे कि वे पार्टिसिपेट कर सकें? चुनाव आयोग का जो प्रपोज़ल बना हुआ था बिहार के बारे में, उसमें आपने गंगा के इस पार और उस पार को जोड़ दिया था, जो हिस्टॉरिक स्थान था। एक कमिश्नरी मुंगेर थी, जिससे सात जिले बने और मुंगेर को हटा दिया और बेगूसराय में मिला दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में कोई विचार करेंगे या नहीं? दिल्ली और पांडिचेरी तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार जैसे बड़े राज्य का भी डीलिटिमिशन हो जाना चाहिए ताकि चुनाव समय पर करने में सुविधा मिले।

SHRI S. REGUPATHY: It is not a question of a big State or a small State. For the purpose of delimitation, seats will not be increased. Same seats allocated for the each State will be in force.

MR. CHAIRMAN : Rationalization and re-adjustment is done on the basis of the existing population. That is the only thing.

. (Interruptions)

SHRI S. REGUPATHY: Similarly, section 43E of the Government of Union Territories Act, 1963, is required to be amended.

**श्री राम कृपाल यादव** : सभापति जी, माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा के प्रश्न का जवाब नहीं आया है। माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया था कि डीलिटेशन की जो समिति बनी थी

.(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is a very simple thing. Only some figures are changed and it is made in conformity with the 1997 amendment. There is nothing to worry about it. This is a very small amendment. Please sit down.

**श्री राम कृपाल यादव** : सभापति महोदय, डीलिटेशन की जो समिति बनी थी, उसके सदस्य सांसद और विधायक होते हैं। सांसद तो उस समिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन चूंकि बिहार में सदस्यों ने अभी शपथ भी नहीं ली है, वे इस समिति में नहीं आ पाते हैं। .(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ झा** : मंत्री जी जवाब तो देंगे कि होगा या नहीं होगा? .(व्यवधान)

SHRI S. REGUPATHY: It is not about the whole country. It is only about New Delhi and Pondicherry. . (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You please address the Chair.

SHRI S. REGUPATHY : Section 43E says: "Notwithstanding anything contained in sections 38 to 43D (both inclusive), until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, it shall not be necessary to readjust the division of each Union Territory into territorial constituencies and any reference to the 'latest census figures' in this part shall be construed as a reference to the 1971 census figures." Amendment to the section will read as under. For the figures "2000", the figures "2026" shall be substituted; and for the figures "1971", the figures "2001" shall be substituted. Besides, with the enactment of the Delimitation Act, 2002, the references made to the Delimitation Commission Act, 1962 under section 38 of the Government of Union Territories Act, 1963 shall be substituted as references to the Delimitation Act, 2002.

Now I come to the amendment to the Government of National Capital Territory Act, 1991. The existing provision of sub-section (3) of section 3 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, provides that seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly, and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the capital bears to the total population of the capital and the provisions of article 334 shall apply to such reservation.

The amended proviso to Explanation will read as under:-

"Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 2001 census."

The purpose of the proposed amendments is to bring the provisions of these Acts in conformity with the Constitutional provisions in regard to delimitation.

MR. CHAIRMAN : Thank you. After all, a simple matter you have dealt with a protracted statement.

Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963 and to amend the Government of National Capital Territory of Delhi, 1991, be taken into consideration. "

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill. "

*The motion was adopted*

*Clauses 2 to 5 were added to the Bill.*

*Clause 1 Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI S. REGUPATHY: I beg to move:

"That the Bill be passed. "

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed. "

*The motion was adopted.*

-----